Rural Industrialisation and Employment Generation

1355. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a work-shop on Rural Industrialisation and Employment Generation involving Members of Parliament was organised from 3rd February to 6th February, 1992 at National Institute of Rural Development at Hyderabad;

(b) if so, what are the recommendations made and the steps taken to implement them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes. A workshop on Rural Industrialisation and Employment Generation was organised from 3rd February to 6th February, 1992 at National Institute of Rural Development, Hyderabad in which twenty seven Members of Parliament participated.

(b) Summary of recommendations made during the workshop on Rural Industrialisation and Employment Generation are given in the Statement (See below). Recommendations need to be examined for further appropriate action.

Statement

Summary of the recommendations of the workshop of Rural Industrialisation and Employment Generation.

1. Evolving a plan for harmonious balance between agricultural growth and rural industrialisation.

2. More rational and equitable distribution a of land assets through land reforms as a vigorous stimulant to rural industrialisation.

3. Imparting special attention to health and family planning so as to ensure that gains of rural industrialisation and rural development are not frittered away.

4. Monitoring of wage employment programmes by an agency set up by the Government.

5. Provision of adequate training facilities to make the IRDP schemes viable.

6. Formation of cooperatives of the producers for specific agricultural products to assist in the acquisition of inputs, processing of output and sale at reasonable prices.

7. Complete de-regulation of rural Industries. However, all regulations in the public interest like pollution control, weights and measures, health regulation etc. be implemented through village Management Committee.

8. Provision of banking facilities and telecommunication within the reach of rural areas.

9. Setting up of an efficient organisation to implement the above recommendations as per the local conditions in different regions of the country.

[1356. *Transferred to the 17th March*, 1992]

सड़कों को गांवों से नहीं जोड़ा जाना

1357. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

श्री रणजोत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में गांवों को मुख्य सड़क-मार्गों से नहीं जोडा गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के अन्त में ऐसे ग्रामों का अनुमानित प्रतिशत कितना था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परिवहन के विकास हेतु आवंटित राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित राशि की तुलना में बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि के आवंटन का प्रस्ताव है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के के दौरान देश के शेष ग्रामों को मुख्य सड़क-मार्गों के साथ जोड़ने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले अनुमानतः 30 प्रतिशत और 1500 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले वाले 13 प्रतिशत गांवों की मुख्य-मार्गों से नहीं जोड़ा गया था। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः देश में परिवहन के विकास के लिए आबंटित धनराशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परिवहन के विकास के लिए निर्धारित परिव्यय निम्न प्रकार था :—

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	12334.55
सड़कें	5200.04
सड़क परिवहन	1990.10
बंदरगाह	1260.42
नौवहन	826.88
अन्तर्देशीय जल परिवहन	225.73
नागरिक उड्डयन	757.84
अन्य	49.30

(ङ) चूंकि आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः शेष गांवों को मार्गों से जोड़ने के लक्ष्य का प्रश्न नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना

1358. **श्री विश्वनाथराव रामराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विकसित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?